गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 260
दि. 21.01.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

आवारा कुत्तों पर बयान से न्यायपालिका की नाराज़गी मेनका गांधी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर दिए गए बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि बिना सोचे-समझे और भावनात्मक आवेश में दिए गए बयान न्यायालय की अवमानना के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि अदालत ने इस मामले में औपचारिक रूप से अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से इनकार करते हुए "दया" दिखाने की बात कही, लेकिन सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों से यह स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को अपने शब्दों और व्यवहार दोनों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। मामला उस समय तूल पकड़ गया जब मेनका गांधी के हालिया पॉडकास्ट में दिए गए कुछ बयानों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। अदालत का मानना था कि इन टिप्पणियों में न सिर्फ न्यायालय के आदेशों की आलोचना की गई, बल्कि भाषा और प्रस्तुति का तरीका भी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि एक पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री से इस तरह की गैर-जिम्मेदार टिप्पणियों की उम्मीद नहीं की जा सकती। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी से जुड़े संदर्भ में यह भी याद दिलाया कि वह केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक सत्ता और प्रशासन का हिस्सा रही हैं। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि जब वह केंद्र सरकार में मंत्री थीं और उनके पास महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय और पशु कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की

जिम्मेदारी थी, तब उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठाए। पीठ ने पूछा कि क्या उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए किसी तरह के बजटीय प्रावधान या नीति-स्तरीय प्रयास किए थे, या फिर अब केवल अदालत के आदेशों पर टिप्पणी करना ही आसान रास्ता चुना जा रहा है।

मेनका गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने पक्ष रखा, लेकिन उनकी दलीलों पर भी अदालत संतुष्ट नहीं दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सीधा सवाल किया कि क्या उन्होंने अपने मुवक्किल के पॉडकास्ट को गंभीरता से सुना है और उसमें कही गई बातों का आकलन किया है। अदालत ने कहा कि गांधी ने लगभग हर किसी के खिलाफ टिप्पणियां की हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज तक पर सवाल उठाए जाने लायक स्थिति पैदा हो गई है। पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत की आलोचना करते समय एक मर्यादा और संतुलन जरूरी होता है, जिसे इस मामले में नजरअंदाज किया गया।

सुनवाई के दौरान माहौल तब और गंभीर हो गया जब जस्टिस विक्रम नाथ ने एक कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अजमल कसाब जैसे आरोपी ने भी अदालत की अवमानना नहीं की थी, लेकिन यहां मामला न्यायालय की गरिमा से जुड़ा हुआ है। इस तुलना के जरिए पीठ ने यह संकेत दिया कि अवमानना का प्रश्न केवल अपराध या व्यक्ति के कद से नहीं, बल्कि व्यवहार और शब्दों की गंभीरता से जुड़ा होता है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मामले में औपचारिक अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं कर रही है, लेकिन यह छूट किसी स्थायी अधिकार की तरह नहीं देखी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व है, लेकिन यह स्वतंत्रता निरंकुश नहीं हो सकती। खासकर जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हो, राजनीतिक पृष्ठभूमि रखता हो और वर्षों तक सरकार का हिस्सा रहा हो, तब उसके बयानों का असर कहीं अधिक व्यापक होता है। अदालत का मानना था कि इस तरह के बयान समाज में भ्रम, टकराव और अविश्वास पैदा कर सकते हैं, खासकर ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जहां एक ओर मानव सुरक्षा और दूसरी ओर पशु अधिकारों का प्रश्न जुड़ा हुआ है। आवारा कुत्तों का मुद्दा देश के कई हिस्सों में लंबे समय से विवाद और चिंता का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि पशु कल्याण और नागरिकों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जा सके। अदालत ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया है कि कानून के तहत ही समाधान निकाला जाना चाहिए और किसी भी तरह की हिंसा या मनमानी स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा इन आदेशों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की जाती है, तो उसका असर केवल बहस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जमीनी स्तर पर भी गलत संदेश जा सकता है। पीठ ने यह भी संकेत दिया कि अगर भविष्य में इस तरह की टिप्पणियां दोहराई गईं, तो अदालत सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। भले ही इस बार "दया" दिखाते हुए कार्यवाही से बचा गया हो, लेकिन यह चेतावनी स्पष्ट है कि न्यायालय की गरिमा से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख न सिर्फ मेनका गांधी के लिए, बल्कि सभी सार्वजनिक हस्तियों के लिए एक संदेश माना जा रहा है कि बोलने की आजादी के साथ-साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सामाजिक मुद्दों पर बहस करते समय भावनाओं और विचारों के बीच संतुलन कैसे रखा जाए। पशु कल्याण जैसे संवेदनशील विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन जब बात सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की हो, तो असहमति भी संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर रहकर ही व्यक्त की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त चेतावनी को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, जहां न्यायपालिका ने साफ कर दिया है कि मर्यादा और जिम्मेदारी से ही लोकतांत्रिक संवाद आगे बढ़ सकता है।

भ्रष्टाचार पर सख्त संदेशः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य पुलिस भी कर सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की जांच

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के मामलों में जांच अधिकारों को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार की जांच एजेंसियां और पुलिस केंद्रीय कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकती हैं और संबंधित अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर सकती हैं। इसके लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से किसी प्रकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यह फैसला न केवल जांच एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करता है, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी उस अपील को खारिज करते हुए की, जिसमें एक केंद्रीय कर्मचारी ने राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी द्वारा की गई जांच को चुनौती दी थी। अदालत ने साफ कहा कि राज्य एजेंसियों द्वारा दाखिल चार्जशीट को केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि जांच के लिए सीबीआई

से अनुमति नहीं ली गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत राज्य पुलिस और विशेष जांच एजेंसियों को भी समान रूप से जांच का अधिकार प्राप्त है। यह मामला राजस्थान से जुड़ा था, जहां केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी नवल किशोर मीणा के खिलाफ राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामला दर्ज किया था। आरोपी कर्मचारी ने तर्क दिया था कि वह केंद्र सरकार का कर्मचारी है, इसलिए उसके खिलाफ केवल सीबीआई ही जांच कर सकती है और राज्य एजेंसी की कार्रवाई कानूनन गलत है। इस दलील के आधार पर उसने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जांच रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी को कोई राहत नहीं दी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देना है। यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी किसी राज्य में तैनात रहते हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा अपराध करता है, तो उस राज्य की पुलिस या भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी को जांच करने से रोका नहीं जा सकता। अदालत ने कहा कि कानून की मंशा यह नहीं है कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराध की जांच केवल एक ही एजेंसी के हाथ में सीमित कर दी जाए। शीर्ष अदालत ने उस दलील को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत केवल सीबीआई को ही केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने और जांच करने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि यह अधिनियम सीबीआई को अधिकार देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि राज्य पुलिस या अन्य एजेंसियों के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कानून की व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती कि वह भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के रास्ते संकुचित कर दे। फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के कई निर्णयों का हवाला भी दिया। अदालत ने कहा कि पहले भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी राज्य में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच राज्य पुलिस या विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, दोनों में से कोई भी कर सकती है। केवल इस आधार पर कि आरोपी केंद्र सरकार का कर्मचारी है, राज्य एजेंसी की जांच को अधिकार क्षेत्र के अभाव में अवैध नहीं ठहराया जा सकता।

इस फैसले को कानूनी विशेषज्ञ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि यदि केंद्रीय कर्मचारियों के मामलों में केवल सीबीआई को ही जांच का अधिकार माना जाता, तो इससे जांच प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल और लंबी हो सकती थी।

बांग्लादेश के छात्र आंदोलन की छाया में न्याय की प्रतीक्षा हत्या मामलों पर आईसीटी-बीडी का फैसला फिर टला

(जीएनएस)। ढाका। बांग्लादेश में वर्ष 2024 के व्यापक छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं से जुड़े बहुचर्चित और संवेदनशील मामले में न्याय की घड़ी एक बार फिर टल गई। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण बांग्लादेश (आईसीटी-बीडी) ने मंगलवार को यह स्पष्ट किया कि वह अभी निर्णय सुनाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अब इस मामले का फैसला 26 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत के इस ऐलान के बाद न सिर्फ पीड़ित परिवारों की उम्मीदें एक बार फिर अधर में लटक गईं, बल्कि पूरे देश में यह बहस भी तेज हो गई कि क्या बांग्लादेश अपने हालिया राजनीतिक और सामाजिक संकटों से उबरते हुए समय पर न्याय सुनिश्चित कर पा रहा है। आईसीटी-बीडी के न्यायमूर्ति गोलाम मोर्तुजा मोजुमदार ने अदालत में फैसले के स्थगन की जानकारी देते हुए कहा कि न्यायाधिकरण को खेद है कि निर्णय अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता, साक्ष्यों की व्यापकता और आरोपों की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायाधिकरण किसी भी प्रकार की

जल्दबाजी नहीं करना चाहता। इसी के साथ अदालत की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और अगली तारीख 26 जनवरी तय की गई। इस घोषणा के समय अदालत कक्ष में मौजूद वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पीड़ितों के परिजनों के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। यह मामला बांग्लादेश के हालिया इतिहास के सबसे अशांत दौर से जुड़ा है। वर्ष 2024 में देश भर में फैला छात्र आंदोलन केवल शिक्षा व्यवस्था या रोजगार की मांग तक सीमित नहीं था, बल्कि वह व्यापक असंतोष का प्रतीक बन गया था। राजधानी ढाका समेत कई बड़े शहरों में छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। सड़कों पर टकराव, पुलिस कार्रवाई, कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी जैसे हालात लंबे समय तक बने रहे। इसी दौरान कई स्थानों पर हुई गोलीबारी और हिंसक घटनाओं में आम नागरिकों और छात्रों की जान चली गई, जिसने सरकार और सुरक्षा बलों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

आईसीटी-बीडी में चल रहे इस मामले में आठ पुलिस अधिकारियों पर मानवता के खिलाफ अपराध के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि छात्र आंदोलन के दौरान की गई पुलिस कार्रवाई में छह लोगों की हत्या हुई, जिनकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर इन अधिकारियों पर आती है। आरोपियों में ढाका के तत्कालीन पुलिस आयुक्त हबीबुर रहमान, पूर्व संयुक्त आयुक्त सुदीप कुमार चक्रवर्ती और छह अन्य वरिष्ठ एवं मैदानी स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल हैं। अभियोजन पक्ष का दावा है कि इन अधिकारियों ने न सिर्फ अत्यधिक बल प्रयोग की अनुमति दी, बल्कि कुछ मामलों में हिंसक कार्रवाई का प्रत्यक्ष आदेश भी दिया। इस मुकदमे का महत्व केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ऐतिहासिक रूप से सत्ता परिवर्तन और नीतिगत बदलावों का बड़ा कारण रहे हैं। ऐसे में 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं पर न्याय का फैसला आने वाले समय में देश की लोकतांत्रिक साख और मानवाधिकार स्थिति को प्रभावित कर सकता है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यदि इस मामले में निष्पक्ष और समयबद्ध फैसला नहीं होता, तो यह संदेश जाएगा कि राज्य के सुरक्षा तंत्र के भीतर जवाबदेही की कमी बनी हुई है। पीड़ित परिवारों के लिए यह मामला केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों, भाइयों या परिजनों को आंदोलन के दौरान खोया, वे पिछले एक साल से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। उनके अनुसार, हर स्थगन उनके घावों को फिर से हरा कर देता है। कई परिजनों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन बार-बार तारीख टलने से उनका धैर्य टूटता जा रहा है।

आईपीएल 2026 से पहले बीसीसीआई का बड़ा दांव, एआई प्रायोजन में गूगल जेमिनी से 270 करोड़ का ऐतिहासिक करार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की तैयारियों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आईपीएल केवल एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर स्पोर्ट्स ब्रांड बन चुका है। बीसीसीआई ने गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जेमिनी के साथ 270 करोड़ रुपये का प्रायोजन करार किया है, जो तीन वर्षों के लिए लागू होगा। यह समझौता तकनीक और खेल के बदलते रिश्ते को दर्शाने के साथ-साथ आईपीएल की वैश्विक अपील और व्यावसायिक ताकत को भी रेखांकित करता है।

बीसीसीआई से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह करार आईपीएल के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है क्योंकि आने वाले वर्षों में एआई और डेटा आधारित तकनीकें खेल जगत में बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। गूगल का जेमिनी प्लेटफॉर्म अब आईपीएल से जुड़कर करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों तक अपनी पहुंच बनाएगा, वहीं बीसीसीआई को एक भरोसेमंद और वैश्विक ब्रांड का साथ मिलेगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि यह साझेदारी आईपीएल को तकनीकी रूप से और अधिक उन्नत बनाने में मदद कर सकती है, जिसमें फैन एंगेजमेंट, एनालिटिक्स और डिजिटल अनुभव को नया आयाम मिल सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि एआई की दुनिया में जेमिनी की प्रतिद्वंद्वी कंपनी चैट जीपीटी पहले से ही महिला प्रीमियर लीग के प्रायोजकों में शामिल है। ऐसे में भारत के दो सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट—आईपीएल और डब्ल्यूपीएल—में एआई प्लेटफॉर्म्स की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि तकनीकी कंपनियां अब क्रिकेट को अपने लिए सबसे प्रभावी मार्केटिंग और ब्रांडिंग मंच के रूप में देख रही हैं। यह प्रतिस्पर्धा केवल मैदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी साफ दिखाई देने लगी है।

बीसीसीआई के लिए यह करार ऐसे समय पर आया है, जब पिछले कुछ वर्षों में प्रायोजन से जुड़े नियमों और नीतियों में बड़े बदलाव हुए हैं। वर्ष 2025 में भारत सरकार द्वारा ड्रीम 11 जैसे वास्तविक धन आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बीसीसीआई को जर्सी प्रायोजन के लिए नए विकल्प तलाशने पड़े थे। उस दौर में कई ब्रांड्स ने सतर्क रुख अपनाया था, लेकिन इसके बावजूद आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में कोई गिरावट नहीं आई। बाद में अपोलो टायर्स ने 579 करोड़ रुपये के भारी-भरकम करार के साथ जर्सी प्रायोजक बनकर यह साबित कर दिया कि आईपीएल से जुड़ना अब भी कंपनियों के लिए एक फायदे का सौदा है।

वर्तमान में टाटा समूह के पास आईपीएल के टाइटल प्रायोजन अधिकार हैं और यह साझेदारी भी आईपीएल की स्थिरता और विश्वसनीयता को दर्शाती है। गूगल जेमिनी के जुड़ने से प्रायोजकों की सूची और मजबूत हुई है, जिसमें ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और कंज्यूमर ब्रांड्स का संतुलित मिश्रण देखने को मिलता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आईपीएल किसी एक सेक्टर पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच हर उद्योग तक फैली हुई है। आईपीएल 2026 का आयोजन 26 मार्च से 31 मई के बीच किया जाएगा और इस बार टूर्नामेंट को लेकर पहले से ही जबरदस्त उत्साह है। नई तकनीकों के जुड़ने से दर्शकों के अनुभव में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि एआई आधारित फीचर्स जैसे स्मार्ट स्टैट्स, पर्सनलाइज्ड कंटेंट, मैच एनालिसिस और रियल टाइम इनसाइट्स को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि बीसीसीआई और गूगल की ओर से अभी इन तकनीकी पहलुओं को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी केवल ब्रांडिंग तक सीमित नहीं रहेगी।

नदी महोत्सव की खुशियां मातम में बदलीं, हीलियम सिलेंडर विस्फोट से एक की मौत, कई परिवारों में पसरा सन्नाटा

(जीएनएस)। कल्लाकुरिची। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में आयोजित थेनपेन्नई नदी महोत्सव के दौरान खुशियों और रंग-बिरंगे उत्साह के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। मनलुरपेट्टई क्षेत्र में गुब्बारों में इस्तेमाल होने वाली हीलियम गैस से भरा एक सिलेंडर अचानक फट गया। इस भीषण विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कम से कम 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद महोत्सव का माहौल चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गया, वहीं प्रशासन और राहत दलों को तुरंत मौके पर पहुंचना पड़ा।

जिला प्रशासन के अनुसार, विस्फोट एक छोटी सी दुकान के अंदर हुआ, जहां हीलियम गैस से भरे गुब्बारे बेचे जा रहे थे। यह दुकान महोत्सव स्थल के बेहद करीब थी और आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जैसे ही सिलेंडर में विस्फोट हुआ, तेज धमाके के साथ आग और धुएं का गुबार उठ गया। आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही कई लोग उसकी चपेट में आ गए। घायल लोग सड़क पर गिर पड़े और कुछ को गंभीर जलन और चोटें आईं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को उठाकर पास के अस्पतालों में पहुंचाने की कोशिश की। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि तिरुवन्नामलाई के जिला कलेक्टर के. थारपगराज ने की। उन्होंने बताया कि घायलों में से कई की हालत गंभीर है और उनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। इससे पहले शुरुआती जानकारी में पुलिस अधिकारियों ने मौत की खबरों को अफवाह बताया था और कहा था कि विस्फोट स्थल पर तीन लोग बेहोश मिले थे, जिन्हें जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। हालांकि बाद में इलाज के दौरान एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, जिससे हादसे की गंभीरता और भी स्पष्ट हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विस्फोट इतना तेज था कि आसपास की दुकानों के शीशे तक हिल गए। लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। बच्चों और महिलाओं में खासा डर देखा गया। कई परिवार अपने परिजनों को खोजते हुए इधर-उधर दौड़ते नजर आए। कुछ ही मिनटों में पूरा उत्सव स्थल मानो ठहर सा गया। जहां कुछ देर पहले तक संगीत, हंसी और उत्सव का माहौल था, वहां अचानक सन्नाटा और दर्द छा गया। यह हादसा उस समय हुआ जब तमिल में 'आत्तु तिरुविझा' कहलाने वाला यह पारंपरिक नदी महोत्सव पूरे शबाब पर था। यह उत्सव तमिल महीने 'थाई' के दौरान, खासतौर पर थाई पूसम के आसपास मनाया जाता है और पोंगल फसल उत्सव के समापन का प्रतीक माना जाता है। विल्लुपुरम, कुड्डालोर और कल्लाकुरिची जैसे जिलों में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह रहता है। दूर-दराज से लोग इस उत्सव में शामिल होने आते हैं, जिससे भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी खड़े हो गए हैं। हादसे के बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। विस्फोट के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि सिलेंडर के रखरखाव या गैस भरने में लापरवाही बरती गई होगी। यह भी जांच की जा रही है कि दुकान संचालक के पास आवश्यक अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। घायलों में से कई को हाथ, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं।

संपादकीय

शांति थोपने की कोशिश

नोबेल शांति पुरस्कार की उत्कट अभिलाषा के मोह में अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के तमाम हिस्सों में जारी अशांति पर शांति थोपने की असफल कोशिश करते रहे हैं। कई देशों में टकराव के बाद शांति की स्थापना की असफल कोशिशों के पश्चात अब ट्रंप गाजा में शांति थोपने का उपक्रम कर रहे हैं। गाजा में शांति स्थापना के लिये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित योजना विश्व की नियामक संस्थाओं के ढांचे से बाहर उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप एक महत्वाकांक्षी कदम है। गाजा में शांति बनाये रखने के लिये मुनाफे व व्यापार जैसी प्रक्रिया के रूप में यह प्रयास अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को एक प्रत्यक्ष चुनौती है। जो लंबे समय से दुनिया के सबसे जटिल संघर्षों में से एक गाजा संकट को दूर करने के प्रयासों में लगी हुई हैं। सही मायनों में ट्रंप का यह शांति प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ को दरकिनार करने जैसा है, जिसको लेकर उन्होंने बार-बार नकारात्मक प्रतिक्रिया दी हैं। उनकी दलील है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अक्षम और पक्षपाती है। वह इसमें अत्यधिक नौकरशाही हावी होने के भी आरोप लगाते रहे हैं। निश्चित तौर पर दुनिया की महाशक्तियां संयुक्त राष्ट्र को हांकने का प्रयास करती रही हैं। वे अपने मनमाफिक न होने पर इसे अक्षम बताने लगते हैं। दरअसल, ट्रंप की कोशिश है कि उसकी मनमाफिक क्षेत्रीय शक्तियां और अमेरिका-संगठित पक्षों द्वारा शांति योजना को सिरे चढ़ाया जाए। निश्चित रूप से यह प्रयास सार्वभौमिक बहुपक्षवाद को नकार कर शासन व्यवस्था बदलने का प्रयास ही है। निर्विवाद रूप से जो शांति, बिना वैधता,सहमति और जवाबदेही के थोपी जाती है, वह कभी स्थायी समाधान का वाहक नहीं बन सकती है। ऐसे में किसी भी विश्वसनीय शांति प्रयास के जरिये उन वास्तविकताओं से निपटना होगा, जिन्हें ट्रंप मनमानी व जल्दबाजी में अकसर नजरअंदाज करते रहे हैं। अन्यथा यह कोशिश भी ट्रंप की अन्य कोशिशों की तरह विफल ही साबित होगी।

आज गाजा संकट जिस मुश्किल दौर में पहुंच चुका है, उसके लिये जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्रियान्वयन, नागरिकों की सुरक्षा और समावेशी शासन का मार्ग प्रभावी समझौते से सुनिश्चित किया जाए। ऐसे हालात में यदि अमेरिका अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को अधिक महत्व देता है या राजनीतिक अधिकारों के बजाय आर्थिक वादों को प्राथमिकता देता है, तो इस प्रयास में उस जोखिम की आशंका बनी रह सकती है, जो जमीनी वास्तविकताओं के बोझ से ढह सकता है। गाजा में शांति के लिये नये प्रयास कसौटी पर तभी खरे उतर सकते हैं जब इसमें गाजा की वास्तविक आवाज को सुना जाता हो। निश्चित रूप से हिंसा पर काबू पाना प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन नागरिकों के जीवन की गरिमा बनाये रखना और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है। शांति समझौते में यदि स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी होती है तो यह शांति प्रस्ताव एक उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि दशकों से हिंसा व विस्थापन का दंश झेल रहे गाजावासियों के कष्टों को और बढ़ाएगा ही। भारत को इस शांति प्रयासों में शामिल करने का प्रस्ताव अमेरिका की ओर से दिया गया है। भारत वहां सदा से ही द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन करता आया है। निर्विवाद रूप से भारत के जहां इस्राइल से बेहतर संबंध हैं, वहीं विश्वसनीयता अरब देशों में भी बरकरार रही है। गाजा में शांति प्रयासों में लगे अरब देशों के साथ भारत के मधुर संबंध रहे हैं। लेकिन यदि शांति प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को नजरअंदाज किया जाता है तो यह भारत की कूटनीतिक पहल के अनुकूल नहीं होगा। निस्संदेह, भारत हमेशा से ही प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बजाय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये बहुपक्षीय मंचों पर ही भरोसा करता रहा है। ऐसे में गाजा में शांति के लिये पहल वैश्विक राजनीति में ट्रंप-प्रेरित उथल-पुथल को ही दर्शाती है। यदि गाजा में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास संयुक्त राष्ट्र को नजरअंदाज करते हैं, तो यह उस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को कमजोर करने का जोखिम बढ़ाएगा, जिसकी जरूरत समझौते के पूरा होने के बाद शांति बनाये रखने के लिये है।

उथल-पुथल के बीच निर्णायक मोड़ पर ईरान

> ईरान में विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन व उन पर सरकार की सख्त प्रतिक्रिया जारी है। ये इस इस्लामी गणराज्य के लिए अस्तित्व को चुनौती प्रतीत होते हैं। ऐसे में वहां सत्ता परिवर्तन की मांग शायद जल्दबाजी हो , लेकिन सरकार के अंदर बदलाव होने लाजिमी हैं।

पिछले करीब तीन सप्ताह में हुए अभूतपूर्व देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों ने इस्लामिक गणराज्य ईरान को हिलाकर रख दिया है। ये जल्द ही रुक जाएंगे, ऐसा कोई संकेत दिखाई नहीं देता। ईरान में सामाजिक अशांति नई बात नहीं, लेकिन हाल में हुए सार्वजनिक प्रदर्शनों की तीव्रता से लगता है कि देश के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है।

इनको फरवरी, 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से, 47 सालों में सत्ता के समक्ष सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। देश में लॉकडाउन के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संचार और टेलीफ़ोन सेवाएं बंद हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ने वैश्विक सैटेलाइट संचार नेटवर्क 'स्टारलिंक' ब्लॉक करने को रूसी या चीनी मिलिट्री ग्रेड तकनीक का इस्तेमाल किया। अफवाहों और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी वाले माहौल में ईरान में मौजूदा स्थिति का सटीक अंदाज़ा मुश्किल है। लेकिन, कई स्रोतों की रिपोर्ट है कि हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने बेरहमी से कार्रवाई की; जिसकी वजह से अब तक बड़ी संख्या में मौतें हो चुकी हैं और हज़ारों लोग हिरासत में लिये। आने वाले दिन या शायद हफ़्ते, तय करेंगे कि व्यापक तौर पर नापसंद मौजूदा सत्ता का भविष्य क्या होगा, हालांकि यह लंबे समय से कायम है और अगले महीने अपने 48वें साल में कदम रखने वाली है।

28 दिसंबर से शुरू होकर, संपूर्ण ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और दंगे हुए। आरंभ तेहरान के ग्रैंड बाज़ार से हुआ। व्यापारी दुकानें बंद कर धरने पर बैठ गए, उनके विरोध की मुख्य वजह थी ईरानी मुद्रा, रियाल का अपने मुख्य मूल्य मापदंड अमेरिकी डॉलर के बरक्स बेतरह गिरना। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की सरकार द्वारा वित्तीय एवं आर्थिक सुधार करने के फैसले ने आग में घी डाल दिया, इसके पीछे हर चीज़ पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध भी एक वजह है। एक प्रस्ताव था कि तरजीही विनिमय दर व्यवस्था

वापस ले ली जाए, जिसके तहत व्यापार संघ, जिन्हें वहां 'बाज़ारी' कहा जाता है, उन्हें भारी सब्सिडी पर बहुत कम दाम पर विदेशी मुद्रा मुहैया करवायी जाती है। ये 'बाज़ारी' नियंत्रित विदेशी मुद्रा प्रणाली के तहत तरजीही सरकारी फंड की उपलब्धता का पूरा बचाव करते आये हैं। पेज़ेशकियन के फैसले ने सत्ताधारी मौलाना वर्ग को इस मुद्दे पर बांट दिया, जो अर्थव्यवस्था पर बाज़ारियों के प्रभाव से परिचित हैं।

जो विरोध प्रदर्शन बाज़ारियों द्वारा दबाव बनाने की तरकीब के तौर पर शुरू हुए, वे जंगल में आग की तरह फैल गए, जिसमें छात्र और समाज का हरेक तबका शामिल हो गया, उनमें हताशा-निराशा लंबे समय से है, खासकर युवाओं में। इसके कुछ कारण हैं, अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार की खस्ता हालत, उच्च महंगाई दर (अनुमानित 45 फीसदी) और सरकार का आर्थिक कुप्रंबधन, भ्रष्टाचार व सरकारी छूट का अनुचित लाभ लेने से लोगों में उपजी निराशा।

ईरान में पिछले विरोध प्रदर्शनों का पैटर्न, जिसमें सबसे ताजा 2022 का हिजाब-विरोधी प्रदर्शन था, कुछ ऐसा रहा कि लोगों की नाराज़गी शुरू में तो किसी सामाजिक (हिजाब-विरोध) या आर्थिक शिकायत से भड़की, लेकिन तुरंत ही सियासी बगावत में बदल गयी। मौजूदा आंदोलन भी उसी पैटर्न पर है। हालांकि, इस बार, विरोध, और विरोध करने वालों की विविधता –जिसमें सभी वर्ग शामिल हैं– भरा विरोध जिस तेजी से फैला वैसी पहले कभी नहीं देखी। एक अतिरिक्त अवयव यह कि फ़लस्तीन, सीरिया व लेबनान के मामले में ईरानी सरकार के दखल से पड़े आर्थिक बोझ पर नाराज़गी खुलकर जाहिर हुई है।

सरकार के खिलाफ़ आम नारा 'तानाशाह को सजाए मौत'जिससे अभिप्राय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई है– के अलावा अब 'न गाज़ा न लेबनान के लिए, मेरी जान है ईरान के लिए' जैसे नारे भी लग रहे हैं। एक नया अवयव है 'जाविद शाह' (शाह अमर रहे) का नारा है, यानी अमेरिका में निर्वासन काट रहे युवराज रेज़ा पहलवी। पहलवी इस बगावत का श्रेय चाहते हैं और खुद को बतौर सही विकल्प पेश कर रहे हैं।

हालांकि ईरान की बिखरी राजनीति और पहलवी की ईरानियों की इस पीढ़ी से दूरी के चलते यह मुश्किल काम लगता है। राजशाही ईरानियों के बीच विवादास्पद मुद्दा है। वर्तमान सामाजिक उथल-पुथल की तीव्रता और उस पर सरकार की जानी-पहचानी सख़्ती ने पश्चिम एशिया के सबसे महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक खिलाड़ियों में एक की अंदरूनी स्थिरता को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। जो हालात बन रहे, वे ईरान के पड़ोसियों के लिए भी गहरी चिंता की वजह होंगे। ईरान पश्चिम एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो भू-रणनीतिक एवं धार्मिक तौर पर अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी, सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। दोनों मुल्क सुन्नी और शिया पंथ की विचारधाराओं के ज़रिए इस्लामिक उम्माह की सरदारी के लिए होड़ में हैं। जबकि इस्लाम के ये दोनों पंथ भारत में शांति के साथ सह-अस्तित्व में हैं, यह परिदृश्य ओआईसी (ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन) के किसी एक भी देश में नजर नहीं आता।

भारत और ईरान के बीच पारंपरिक रूप से करीबी ऐतिहासिक रिश्ते रहे और हाल के वर्षों में और प्रगाढ़ हुए, खासकर भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट के प्रबंधन एवं परिचालन की भागीदारी के जरिये। ब्रिक्स और एससीओ की सदस्यता दोनों देशों को सहयोग बढ़ाने देने में मददगार है। अकसर इस बात को कम आंका जाता है कि ईरान ने दशकों वाणिज्यिक और आर्थिक प्रतिबंध झेले, फिर भी कुशलता से खुद को अलग-थलग पड़ने से बचाने में कामयाब रहा। ईरान अपनी आज़ादी कायम रखने को कटिबद्ध है और वैश्विक ऊर्जा बाज़ार सहित एक महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह बनाए है। इसके पास कच्चे तेल का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। ईरान काफी मांग वाले अपने हल्के तेल, यानी कम सल्फर मात्रा वाले कच्चे तेल, का प्रतिदिन लगभग दो मिलियन बैरल निर्यात करता है। इस प्रकार, ईरान में विरोध प्रदर्शनों और वेनेजुएला में हुई असामान्य घटनाओं ने दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी ला दी, ऐसी बढ़ोतरी जिस पर भारत के नीति निर्माता आगामी केंद्रीय बजट से पहले करीबी नज़र रखेंगे।

फिलहाल, ईरान में हालात बेहद अस्थिर हैं। इराक की सीमा से लगे ईरान के उन प्रांतों में स्थिति खासकर गंभीर लग रही है जो कुर्द-बहुल हैं। फिलहाल इस्लामिक शासन में फूट के संकेत नहीं दिखे व सर्वोच्च नेता ने समझौता करने या लोगों से संपर्क की इच्छा नहीं जताई। पेजेशकियन शुरू में सुलह के इच्छुक लगे, लेकिन फिर पीछे हट गए। भारत आम तौर पर ऐसे अवसरों पर सावधान रहा है, महज एक छोटी ट्रैवल एडवाइज़री जारी की है और किसी भी सार्वजनिक ब्यान से परहेज़ किया। आख़िर, ईरान में लगभग 3,000 भारतीय छात्र हैं, जिनमें क़ोम व मशाद के धार्मिक मदरसों के तालिब भी शामिल हैं, और यह सावधानी ज़रूरी है।

दूसरी ओर, ज़्यादातर पश्चिमी देशों की आधिकारिक टिप्पणियों में ईरानी अधिकारियों की कड़ी प्रतिक्रिया की निंदा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे लेकिन यह दावा भी कर रहे कि उन्हें फिर से ईरान से वार्ता संदेश मिले हैं। घटनाक्रम पर नज़र रखने वाले जानते हैं कि अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में फिर से रणनीतिक बॉम्बर हवाई जहाज़ तैनात कर दिए, इसी सैन्य अड्डे से उसने पिछले जून में 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' चलाया था।

जहां सत्ता परिवर्तन की मांग समयपूर्व और जल्दबाज़ी हो सकती है, लेकिन संभव है सरकार के अंदर बदलाव की शुरुआत हमें देखने को मिले। ईरान में किसी भी किस्म की अस्थिरता के इस क्षेत्र और ऊर्जा मार्केट, दोनों पर, गंभीर असर होंगे।

प्रेरणा

ज्ञान की अनंतता: प्लेटो से सीखें विद्या का असली स्वरूप

मानव सभ्यता के इतिहास में ज्ञान और विद्या की खोज हमेशा से ही सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। ज्ञान का अर्थ केवल किताबी शिक्षा या सूचना नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक गहराई और जीवन में इसके अनुप्रयोग में छिपा है। इस संदर्भ में ग्रीस के महान दार्शनिक प्लेटो का जीवन और उनके विचार आज भी आधुनिक समाज और शिक्षा प्रणाली के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्लेटो, जो कि अपनी सोच, तार्किकता और दार्शनिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, केवल विद्वान नहीं थे, बल्कि ज्ञान की वास्तविक अनंतता को समझने वाले ज्ञानी भी थे।

प्लेटो का जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता। यह एक सतत यात्रा है, जो न केवल दूसरों से सीखने में बल्कि अपने भीतर झांकने और स्वयं के अनुभवों को समझने में भी निहित है। कहा जाता है कि प्लेटो हर क्षण कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहते थे। उनके पास प्रायः शीर्षस्थ बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, दार्शनिक और जिज्ञासु उनके पास पहुंचते, अपने विचार साझा करते और ज्ञान प्राप्त करने के नए आयाम तलाशते। प्लेटो भी हर आगंतुक से सीखने की कोशिश करते, चाहे वह उनके विषय में छोटा ज्ञान रखता हो या बड़ा। उनके लिए ज्ञान का स्रोत किसी के पद या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की सोच और अनुभव से निर्धारित होता था।

एक प्रसंग इस दृष्टि से अत्यंत शिक्षाप्रद है। एक दिन प्लेटो ने विज्ञान के एक शिक्षक की अध्यात्म संबंधी जिज्ञासा का समाधान किया। शिक्षक की जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि उसने अपनी समस्याओं और प्रश्नों का समाधान पाने के लिए प्लेटो से मार्गदर्शन मांगा। प्लेटो ने शिक्षक की हर बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसे स्पष्ट उत्तर दिया। अध्यात्म और तर्क के इस मिश्रण में शिक्षक संतुष्ट हुआ और विदा होने ही वाला था कि प्लेटो ने उससे एक साधारण सा प्रश्न पूछा—'आप मुझे विज्ञान से संबंधित कुछ नया ज्ञान बताएँ।' शिक्षक आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, इतना बड़ा दार्शनिक, जो पहले ही ज्ञान में इतना उच्च स्तर प्राप्त कर चुका है, अब भी दूसरों से सीखने का प्रयास कर रहा है।

शिक्षक के चले जाने के बाद उनके शिष्य ने प्लेटो से पूछा, 'सर! आप संसार के प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक हैं। जब आप आगंतुकों से कुछ पूछते हैं, तो हमें ग्लानि महसूस होती है। आप इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद ऐसा क्यों करते हैं?' शिष्य की जिज्ञासा सहज और मानव स्वाभाविक थी। वह सोच रहा था कि प्लेटो जैसे महान दार्शनिक के लिए दूसरों से सीखने की आवश्यकता क्यों हो सकती है।

प्लेटो ने बड़े सहज और सरल शब्दों में उत्तर दिया, 'वत्स, ज्ञान अथाह है। उसकी कोई सीमा नहीं होती। मेरा ज्ञान भी उतना ही सीमित है, जितनी समुद्र की एक बूंद। पूर्ण ज्ञानी होने का कोई दावा नहीं कर सकता। जो ऐसा करता है, वह झूठा और अहंकारी होता है।' इस उत्तर में न केवल ज्ञान की अनंतता का भाव व्यक्त हुआ, बल्कि अहंकार से मुक्त होने का महत्वपूर्ण संदेश भी निहित था। प्लेटो का यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ केवल तथ्यों और सूचनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि विनम्रता और सीखने की अनवरत प्रक्रिया में है।

ज्ञान की यात्रा में विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि उसने सारी विद्या अर्जित कर ली, तो वह वास्तविकता से कोसों दूर है। क्योंकि हर विज्ञान, हर दर्शन और हर अनुभव का क्षेत्र निरंतर विकसित होता है। जैसे समुद्र में हर बूंद अलग होती है, वैसे ही ज्ञान की हर नई खोज और हर नई समझ मानव जीवन के लिए नए अवसर और नई सोच लेकर आती है। प्लेटो की यह शिक्षा आज के समय में और भी प्रासंगिक है, जब दुनिया में सूचना और डेटा की विशाल मात्रा उपलब्ध है। केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे समझने, लागू करने और विनम्रता के साथ साझा करने की कला ज्ञान की सच्ची पहचान है। प्लेटो का दृष्टिकोण यह भी दर्शाता है कि ज्ञान केवल पढ़ाई और शिक्षा तक सीमित नहीं है। यह जीवन अनुभव, संवाद और दूसरों के दृष्टिकोण से सीखने में भी निहित है। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखना, चाहे वह छोटा ज्ञान रखता हो या बड़ा, यह विद्या का असली स्वरूप है। इसी लिए प्लेटो ने स्वयं अपने ज्ञान को समुद्र की एक बूंद के समान समझा और दूसरों से सीखने में कभी संकोच नहीं किया।

आज के समय में, जब व्यक्ति केवल प्रमाणपत्र और डिग्रियों के आधार पर खुद को ज्ञानी मानने लगा है, प्लेटो का यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि ज्ञान की वास्तविक परख अनुभव और विनम्रता से होती है। यदि हम यह समझ लें कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, तो हम जीवन में निरंतर विकास और सुधार की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

प्लेटो के विचार हमें यह भी स्मरण कराते हैं कि ज्ञान केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। इसे साझा करना और दूसरों को मार्गदर्शन देना भी विद्या का अनिवार्य हिस्सा है। जैसे प्लेटो आगंतुकों से सीखते थे, वैसे ही उन्हें मार्गदर्शन भी देते थे। इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष—सीखने वाला और सिखाने वाला—समान रूप से लाभान्वित होते थे। ज्ञान का आदान-प्रदान केवल जानकारी का लेन-देन नहीं, बल्कि मन और चेतना का विस्तार है।

इस दृष्टि से, प्लेटो का जीवन आज भी प्रेरणा देता है। हमें अपने जीवन में यह समझना होगा कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर नई परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाने की क्षमता रखती है। इस सीख के साथ हम न केवल अपने ज्ञान का दायरा बढ़ा सकते हैं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मूल्यवान योगदान दे सकते हैं।

अंततः, ज्ञान की अनंतता यह बताती है कि ज्ञान का असली स्वरूप विनम्रता, सीखने की निरंतरता और दूसरों के अनुभवों को अपनाने में छिपा है। प्लेटो ने इसे जीवन में पूरी तरह से अपनाया और इसी लिए वे न केवल दार्शनिक थे, बल्कि ज्ञान के सच्चे साधक भी बने। उनके दृष्टांत से हमें यह समझना चाहिए कि ज्ञान का असली मूल्य किसी प्रमाणपत्र या उपाधि में नहीं, बल्कि सीखने की निरंतर यात्रा में और दूसरों के साथ साझा करने में निहित है।

ममता बनर्जी को केद्र सरकार से टकराने का बहाना चाहिए

पश्चिम बंगाल देश के लिए ऐसा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। इससे होने वाले राष्ट्रव्यापी नुकसान की ममता बनर्जी सरकार को परवाह नहीं है। ममता बनर्जी का तौर—तरीका ऐसा बन चुका है मानो पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं होकर एक स्वतंत्र देश हो। ममता किसी न किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार से टकराती रही हैं। एक भी मौका केंद्र से टकराव का नहीं छोड़ती है और फिर खुद ही लोकतंत्र खतरे में है का नारा देकर सिर पर आसमान उठा लेती है। नया मामला प्रवर्तन निदेशालय के छापे की कार्रवाई का है। ईडी ने पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दूसरी टीम सॉल्टलेक स्थित दफ्तर पर छापा मारा था। सीएम ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट पहुंच गई। जब बाहर निकलीं, तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद ऑफिस भी गईं। उन्होंने कहा-गृहमंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। ममता बनर्जी ने आई-पैक के कार्यालय और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के संबंध में संघीय एजेंसी के खिलाफ दो कोलकाता और बिधाननगर पुलिस ने औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कराई। ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के खिलाफ कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के साथ विरोध मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी चुनाव से पहले उनकी पाटी तृणमूल कांग्रेस के संवेदनशील दस्तावेज जब्त कर राजनीतिक प्रतिशोध कर रही है। पुलिस ने ममता बनर्जी की शिकायत पर ईडी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर औपचारिक जांच शुरू कर दी। यह मुद्दा कलकत्ता हाईकोर्ट तक गया। कलकत्ता हाइकोर्ट ने रेड मामले में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी ईडी ने आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। एजेंसी का कहना था कि पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। कोर्ट ने कहा, जब ईडी ने कुछ भी जब्त न करने की बात की है, तो अब इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचता है। याचिका को खारिज कर दी।

अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर भारतीय न्याय संहिता के तहत 17 अपराधों की सीबीआई जांच की मांग की। याचिका में ईडी ने आरोप लगाया है कि सीएम ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने ईडी की रेड में न सिर्फ बाधा डाली बल्कि अधिकारियों को डरा-धमकाकर सबूतों से छेड़छाड़ की। ममता सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि यह मामला चुनावों के बीच उठाया गया है और इससे राजनीतिक माहौल प्रभावित हो सकता है। ईडी चुनावी डेटा चुराने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सवाल किया, "क्या लॉर्डशिप को लगता है कि हाईकोर्ट न्याय नहीं कर सकता? इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा, "कृपया हमारे मुंह में शब्द न डालें। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले को "गंभीर" करार दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह एक गंभीर मामला है। हम इस पर परीक्षण करेंगे। अदालत ने ईडी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया।

ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से टकराने की फेहरिस्त काफी लंबी है। इसका नमूना कोरोना महामारी में केंद्र के साथ टकराव, अम्फन तूफान को लेकर गृह मंत्री के साथ झगड़ा शामिल है। इस क्रम में बंगाली प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच टकराव को कौन भूल सकता है। बंगाल की सीमा पर नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से आने वाले ट्रकों को लेकर भी केंद्र और बंगाल सरकार के बीच टकराव हुआ था। हुगली के तेलिनीपाड़ा में हुए दंगे को लेकर सोशल मीडिया में सवाल उठाने पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ हुई रिपोर्ट पर राज्य पुलिस ने सांसद अर्जुन सिंह और लॉकेट बनर्जी समेत कई नेताओं पर मामले दर्ज कर एक और टकराव को जन्म दिया था।

टकराव की इस कड़ी में नया मामला पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति का है।राज्य के मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार का कार्यकाल इसी महीने 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। यूपीएससी ने ममता सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट को वापस लौटा दिया। यूपीएससी ने राज्य सरकार की सिफारिश को तकनीकी और कानूनी आधार पर रिजेक्ट कर दिया। दरअसल राज्य सरकार ने नए डीजीपी के चयन के लिए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भेजे थे। लेकिन आयोग ने इस लिस्ट पर विचार करने से ही इनकार कर दिया। यूपीएससी का कहना है कि पुरानी प्रक्रियाओं में कई खामियां छोड़ी गई थीं। इसके चलते वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया को सही नहीं माना जा सकता है। नियमों के मुताबिक सरकार को एक तय समय सीमा के भीतर यह लिस्ट भेजनी चाहिए थी। यूपीएससी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए। अब यह मामला कानूनी पेचीदगियों में बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। सरकार के सामने अब कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा।

गौरतलब है कि पूर्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आगवानी तक के लिए नहीं आई और ना ही बैठक में शामिल हुई। पीएम का दौरा तूफान यास से हुए नुकसान का आकलन करना था। ओडिशा और बंगाल का दौरा तय हो जाने के बाद, दोनों मुख्यमंत्रियों को साथ ही समय बताया गया था। लेकिन ओडिशा ने उस कार्यक्रम के सभी प्रोटोक़ॉल का पालन किया जबकि वो पीएम के बंगाल के दौरे से पहले था।

अभियान

आस्था का चिकित्सालय: भिंड के डॉक्टर हनुमान की अनोखी गाथा

भारत की धरती को सदियों से आस्था, विश्वास और चमत्कारों की भूमि माना गया है। यहां मंदिर केवल ईंट-पत्थरों के ढांचे नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदों और भावनाओं के जीवंत केंद्र होते हैं। इन्हीं अनगिनत धार्मिक स्थलों के बीच मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित दंदरौआ धाम का विशेष स्थान है। यह वह मंदिर है जहां हनुमान जी को साधारण देवता के रूप में नहीं, बल्कि डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है। देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि यहां बजरंगबली स्वयं रोगों का उपचार करते हैं और निराश हो चुके मरीजों के जीवन में नई रोशनी भर देते हैं। भिंड का यह मंदिर अन्य हनुमान मंदिरों से बिल्कुल अलग पहचान रखता है। सामान्यतः हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, पर दंदरौआ धाम में उनका स्वरूप करुणा और उपचार से जुड़ा है। यहां स्थापित प्रतिमा नृत्य मुद्रा में है, जो जीवन के उल्लास और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के मन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। लोगों का कहना है कि जैसे ही वे मंदिर के प्रांगण में कदम रखते हैं, उनके भीतर छिपा भय और निराशा धीरे-धीरे कम होने लगती है।

इस धाम की प्रसिद्धि के पीछे एक मार्मिक कथा छिपी है। बताया जाता है कि वर्षों पहले शिवकुमार दास नामक एक साधु कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित थे। चिकित्सा के तमाम प्रयास विफल हो चुके थे और उनके जीवन की आशा लगभग समाप्त हो गई थी। उसी कठिन समय में उन्होंने हनुमान जी की शरण ली। मान्यता है कि एक रात बजरंगबली स्वयं डॉक्टर के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उनके गले में आला था, शरीर पर सफेद कोट और चेहरे पर अपार करुणा का भाव। उन्होंने साधु का उपचार किया और कुछ ही समय में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इसी घटना के बाद से यहां हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान कहकर पुकारा जाने लगा और मंदिर आस्था के चिकित्सालय के रूप में प्रसिद्ध हो गया।

धीरे-धीरे यह खबर दूर-दूर तक फैल गई। जो लोग असाध्य रोगों से जूझ रहे थे, वे उम्मीद की डोर थामे इस धाम तक आने लगे। किसी को कैंसर था, किसी को टीबी, किसी को जोड़ों का दर्द तो कोई मानसिक अवसाद से घिरा था। भक्तों का अनुभव रहा कि यहां आने के बाद केवल शरीर ही नहीं, मन भी हल्का हो जाता है। बहुत से लोग बताते हैं कि डॉक्टरों से निराश होने के बाद उन्हें सबसे पहले मानसिक संबल यहीं मिला। उनका विश्वास है कि जैसे चिकित्सक रोगी की नब्ज पकड़कर बीमारी समझता है, वैसे ही हनुमान जी भक्त के मन की पीड़ा को बिना कहे जान लेते हैं।

ग्वालियर से लगभग सत्तर किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर आज एक विशाल आस्था केंद्र बन चुका है। हर मंगलवार और शनिवार को यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लंबी कतारों में खड़े लोग अपने साथ नारियल, सिंदूर और प्रसाद तो लाते ही हैं, कई लोग अपनी मेडिकल रिपोर्ट और दवाइयों की पर्चियां भी प्रतिमा के सामने रख देते हैं। उनका विश्वास है कि बजरंगबली इन कागजों के माध्यम से उनकी बीमारी को समझते हैं और उपचार का मार्ग खोलते हैं। यह दृश्य आधुनिक चिकित्सा और आध्यात्मिक विश्वास के अद्भुत संगम जैसा प्रतीत होता है।

मंदिर की विशेषता यह भी है कि यहां पूजा पद्धति बेहद सरल है। किसी महंगे अनुष्ठान या दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही सबसे बड़ा चढ़ावा मानी जाती है। पुजारियों का कहना है कि यहां चमत्कार से अधिक श्रद्धा काम करती है। जब व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करता है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा जागती है, जो रोग से लड़ने की ताकत देती है। यही कारण है कि अनेक मरीज चिकित्सा के साथ-साथ यहां की आध्यात्मिक शक्ति से भी लाभान्वित होते हैं।

दंदरौआ धाम केवल शारीरिक रोगों के लिए ही नहीं, मानसिक पीड़ा के लिए भी बड़ा सहारा है। आज के समय में तनाव, अकेलापन और निराशा तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह मंदिर लोगों को भावनात्मक सुरक्षा देता है। कई युवा बताते हैं कि यहां आकर उन्हें जीने का नया उत्साह मिला। किसी की नींद लौट आई, किसी का डर खत्म हो गया और किसी को परिवार के साथ संबंध सुधारने की प्रेरणा मिली। इसीलिए भक्त इसे मन का अस्पताल भी कहते हैं, जहां दवाइयों से ज्यादा दुआओं का असर होता है।

मंदिर परिसर में आने वाले लोगों के बीच अद्भुत अपनापन देखने को मिलता है। अनजान लोग भी एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई किसी गरीब मरीज की दवा का खर्च उठा देता है तो कोई दूर से आए परिवार को भोजन करा देता है। इस तरह यह धाम केवल धार्मिक स्थल नहीं, मानवीय संवेदनाओं का केंद्र भी बन गया है। यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ थोड़ी उम्मीद और ढेर सारा विश्वास लेकर लौटता है।

कई चिकित्सक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मरीज के ठीक होने में मानसिक शक्ति की बड़ी भूमिका होती है। अगर मन में आशा जाग जाए तो शरीर उपचार को जल्दी स्वीकार करता है। दंदरौआ धाम यही काम करता है। यहां मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा दवाइयों के असर को बढ़ा देती है। यही कारण है कि अनेक लोग चिकित्सा के साथ-साथ इस आध्यात्मिक सहारे को भी अपनाते हैं।

समय के साथ मंदिर की ख्याति मध्य प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे देश में फैल चुकी है। सोशल मीडिया और लोगों के अनुभवों ने इसे और प्रसिद्ध कर दिया है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। कई परिवार तो पीढ़ियों से यहां आ रहे हैं। उनका कहना है कि बजरंगबली ने उनके घरों को टूटने से बचाया, बीमार बच्चों को नया जीवन दिया और निराश मनों में साहस भरा।

यह मंदिर हमें यह भी सिखाता है कि उपचार केवल दवाइयों में सीमित नहीं होता। इंसान शरीर, मन और आत्मा का मेल है। जब तीनों एक साथ मजबूत होते हैं तभी पूर्ण स्वास्थ्य संभव है। डॉक्टर हनुमान का यह धाम इसी संतुलन का प्रतीक है। यहां आने वाला व्यक्ति यह महसूस करता है कि जीवन में सबसे बड़ी दवा विश्वास है।

भिंड के डॉक्टर हनुमान की गाथा केवल चमत्कारों की कहानी नहीं, बल्कि मानव मन की अद्भुत शक्ति की दास्तान है। यह धाम बताता है कि जहां उम्मीद जिंदा रहती है, वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। आज भी जब कोई निराश मरीज मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है तो उसके मन में यही भरोसा होता है कि बजरंगबली उसे खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। यही भरोसा इस मंदिर की असली ताकत है और शायद यही कारण है कि दंदरौआ धाम आस्था के महासागर की तरह दिन-ब-दिन और गहरा होता जा रहा है।

इस पवित्र स्थल की यात्रा करने वाला हर व्यक्ति एक नई अनुभूति लेकर लौटता है। कोई इसे ईश्वर का चमत्कार कहता है, कोई मनोबल की जीत, तो कोई श्रद्धा का प्रभाव। नाम चाहे जो हो, पर इतना निश्चित है कि भिंड का यह मंदिर लाखों लोगों के जीवन में उजाला भर रहा है। डॉक्टर हनुमान की यह अनोखी परंपरा हमें याद दिलाती है कि इंसान जब विश्वास और प्रयास को साथ लेकर चलता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

कच्छ की सरहद डेयरी में है भारत का प्रथम कैमल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, ऊँटनी के दूध की राजभोग आइसक्रीम बनाने वाली देश की एक मात्र डेयरी

▸▸ सहकार से समृद्धि : सरहद डेयरी ने 900 दूध मंडलियों तथा 31,067 पशुपालकों के बैंक खाते खोले, 438 मंडलियों को माइक्रो एटीएम मिले

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भूकंप के बाद कच्छ की हुई कायापलट, सहकारिता क्षेत्र में सरहद डेयरी लाई सकारात्मक परिवर्तन

(जीएनएस)। गांधीनगर : 26 जनवरी, 2001 को आए विनाशकारी भूकंप ने कच्छ को इस हद तक तबाह किया कि हरेक के मन में प्रश्न था कि कच्छ फिर से उठ खड़ा हो पाएगा या नहीं। हालाँकि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस प्रदेश की ऐसी कायापलट हुई कि कच्छ विकास, आत्मनिर्भरता तथा सहकारी समृद्धि का उत्तम उदाहरण बन गया है। उनके नेतृत्व में कच्छ पर्यटन, कृषि, सहकारिता जैसे क्षेत्रों में अग्रसर जिला बना है। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में कच्छ की विकास यात्रा को और गति मिली है। उल्लेखनीय है कि भूकंप के बाद कच्छ के सहकारिता क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में 'श्री कच्छ जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ' यानी सरहद डेयरी की उल्लेखनीय भूमिका रही है। 2009 में श्री वलमजी हुंबल द्वारा स्थापित सरहद डेयरी कच्छ की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है और जिले के पशुपालकों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है।

सरहद डेयरी 80,000 दूध उत्पादकों से प्रतिदिन 5.5 लाख लीटर दूध प्राप्त करती है

सरहद डेयरी 900 से अधिक सहकारी मंडलियों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 80,000 दूध उत्पादकों से लगभग 5.5 लाख लीटर दूध एकत्र करती है। डेयरी में प्रतिदिन 4 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग होती है और यहाँ 300 टन क्षमता का पशु आहार (कैटल फीड) प्लांट भी है। इसके अतिरिक्त; डेयरी द्वारा प्रतिदिन 50,000 लीटर आइसक्रीम भी बनाई जाती है, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन 3.38 लाख लीटर प्रतिदिन दर्ज हुआ है। डेयरी द्वारा पशुपालकों को प्रतिदिन अनुमानित 3 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान सरहद डेयरी ने 1,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऐतिहासिक टर्नओवर हासिल किया है, जो वार्षिक 9.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सरहद डेयरी हरियाणा, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अमूल के डेयरी प्लांट को भैंस के शुद्ध दूध की आपूर्ति करने में भी अग्रसर है।

'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार कर रही है सरहद डेयरी

'सहकार से समृद्धि' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की एक दूरदर्शी पहल है। इस कार्यक्रम अंतर्गत सरहद डेयरी ने कच्छ जिला मध्यस्थ सहकारी (केडीसीसी) बैंक में 900 दूध मंडलियों तथा 31,067 पशुपालकों की बैंक खाते खोलने में सहायता की है। बैंकिंग को अधिक सरल बनाने के लिए किसानों को रुपे कार्ड दिए गए हैं और 438 दूध मंडलियों को माइक्रो एटीएम प्राप्त हुए हैं।

सरहद डेयरी में है भारत का प्रथम कैमल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट

कच्छ के रण का सफेद सोना माने जाने वाले ऊँटनी के दूध में भरपूर खाद्य खनिज तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायी हैं और रोगप्रतिकारक शक्ति में वृद्धि करते हैं। भारत का सर्वप्रथम ऊँटनी के दूध को दुर्गंधमुक्त करने का प्रोसेसिंग प्लांट कच्छ में यानी सरहद डेयरी के पास है, जो 16 जनवरी 2019 से कार्यरत है। ऊँटनी के दूध के लिए प्राथमिक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी सरहद डेयरी ने प्राप्त किया है। कच्छ जिले में रापर, नखत्राणा, गढशीशा तथा कोटडा आथमणा; इन चार कलेक्शन केन्द्रों के माध्यम से ऊँटनी के दूध का अमूल पैटर्न के अनुसार कलेक्शन किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान ऊँटनी के दूध का दैनिक संग्रहण 4,754 लीटर हुआ है। ऊँटनी का दूध जमा कराने वाले ऊँटपालकों को वार्षिक 8,72,83,440 रुपए का भुगतान किया गया है, जिससे 350 से अधिक ऊँटपालक परिवारों को लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त; समग्र भारत में ऊँटनी के दूध की राजभोग फ्लेवर की आइसक्रीम केवल सरहद डेयरी में ही बनाई जाती है। 22 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस आइसक्रीम प्लांट का उद्घाटन किया गया था और इस प्लांट द्वारा केवल एक ही वर्ष में 80 वेराइटी लॉन्च की गई हैं। वर्ष 2024-25 में कुल 24.52 लाख लीटर आइसक्रीम का उत्पादन किया गया और अधिकतम् डिसपैच 58,000 लीटर दर्ज हुआ है।

सरहद डेयरी को मिली है वैश्विक पहचान

जनवरी 2022 में गांधीनगर में इंडियन डेयरी एसोसिएशन (आईडीए) कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी; जिसमें सरहद डेयरी ने भाग लिया था, तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन (आईडीएफ) द्वारा केरल राज्य के कोच्चि में विश्व में पहली बार आयोजित रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस 2024 में विश्व में ऊँट तथा ऊँटनी के विषय पर आयोजित एक महत्वपूर्ण सत्र में सरहद डेयरी द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऊँटनी के दूध की प्रोसेसिंग तथा उत्पादों में किए गए उत्कृष्ट कामकाज का विश्व स्तर पर संज्ञान लिया गया। इसी प्रकार; सरहद डेयरी को 2025 में दुबई में आयोजित विश्व के सबसे बड़े फूड शो 'गल्फ फूड एक्सपो' में भी वैश्विक स्तर पर पहचान मिली, जहाँ अमूल के स्टॉल पर ऊँटनी के दूध के उत्पादकों ने विशेष आकर्षण जमाया। सरहद डेयरी को उसके प्रशंसनीय कामकाज के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं; जिनमें सामाजिक विकास तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए FOKIA Award 2014, कच्छ डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए रोटरी क्लब वॉकेशनल एक्सीलेंस अवॉर्ड 2017, एग्रीटेक में उत्कृष्टता के लिए FOKIA Award 2024 तथा टिकाऊ प्रदर्शन के लिए VNM TV की ओर से ग्रीन वर्कप्लेस अवॉर्ड 2025 शामिल हैं।

चलती ट्रेन में छूटा यात्री का बैग वाणिज्य विभाग एवं आरपीएफ की सतर्कता से सुरक्षित मिला

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल से संचालित ट्रेन संख्या 11465 वेरावल–जबलपुर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री का बैग ट्रेन से उतरते समय छूट गया, जिसे वाणिज्य विभाग के कर्मचारी एवं रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की तत्परता से सुरक्षित कर यात्री को सौंप दिया गया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यात्री श्री अशोक भाई चंद्रवाडिया, निवासी उपलेटा, दिनांक 19.01.2026 को गाड़ी संख्या 11465 के कोच बी-2 में राजकोट से चांदलोडिया की यात्रा कर रहे थे। चांदलोडिया स्टेशन पर उतरते समय उनका एक बैग दरवाजे पर ही छूट गया।

ड्यूटी पर तैनात चल टिकट निरीक्षक (टीटीआई) श्री एम. एफ. अकरम ने लावारिस अवस्था में बैग को देखकर यात्रियों से उसके संबंध में पूछताछ की। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उन्होंने तत्काल आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ एस्कॉर्ट स्टाफ श्री मनीष जाट एवं श्री बदन सिंह ने तत्परता से

कार्रवाई करते हुए बैग को सुरक्षित कब्जे में लिया और नियमानुसार जांच की। जांच के दौरान बैग में लगभग 50,000 नकद एवं अन्य आवश्यक सामान पाया गया। बैग की कुल अनुमानित कीमत लगभग 52,000 थी।

पीएनआर एवं उपलब्ध संपर्क विवरण के आधार पर यात्री से संपर्क कर उन्हें सूचना दी गई। आवश्यक औपचारिकताओं के पश्चात यात्री को अहमदाबाद बुलाकर बैग एवं समस्त सामग्री सुरक्षित रूप से सुपुर्द की गई।

यात्री श्री अशोक भाई चंद्रवाडिया ने आरपीएफ एवं टीटीआई की ईमानदारी, सतर्कता एवं सराहनीय कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने भावनगर मंडल के कर्मचारियों की सतर्कता एवं ईमानदारी की सराहना करते हुए कहा कि पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल अपने सम्मानित यात्रियों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

भावनगर मंडल में दिवंगत रेल कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता

(जीएनएस)। भावनगर मंडल में रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों, विशेषकर रेल सेवा के दौरान आकस्मिक निधन की स्थिति में त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंडल प्रशासन द्वारा डिविजनल स्टाफ रिलीफ एंड वेलफेयर फंड (DSRWF) का गठन किया गया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 20 जनवरी 2026 को रेल सेवा के दौरान निधन होने वाले 08 रेल कर्मचारियों के परिवारों को प्रत्येक परिवार हेतु 50,000/- (पचास हजार रुपये) की सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। यह चेक DSRWF के संरक्षक एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के कर-कमलों से वितरित किए गए। इसके अलावा परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु जरूरी आवेदन और कार्यवाही, HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करने के संदर्भ में मार्गदर्शन भी दिया गया ।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तथा वे स्वयं भी उपस्थित रहे। मंडल प्रशासन द्वारा दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि रेलवे अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहेगा।

ऑपरेटिंग विभाग की टीम बनी डीआरएम कप-2026 चैम्पियन

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल की ऑपरेटिंग विभाग की टीम ने डीआरएम कप 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। प्रतापनगर में माधव राव सिंधिया स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में ऑपरेटिंग विभाग की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग की टीम को 7 विकेट से हराकर डीआरएम कप पर कब्ज़ा किया।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 08 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 तक आयोजित इस टूर्नामेंट में वडोदरा मंडल के विभिन्न विभागों की कुल 16 टीमों ने खेल भावना के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच विद्युत(ट्रैक्शन)विभाग एवं ऑपरेटिंग विभाग की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें ऑपरेटिंग विभाग की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और "डीआरएम ट्रॉफी–2026" की चैम्पियन बनी।

वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक एवं वडोदरा मंडल खेलकूद संघ के अध्यक्ष श्री राजू भडके ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की और साथ ही टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मोमेंटो एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि रेल कर्मियों को अपनी ड्यूटी के साथ-साथ खेलकूद गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए, जिससे वे स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें।

इस प्रतियोगिता में सुरक्षा विभाग के श्री मीठाभाई को बेस्ट बॉलर एवं ऑपरेटिंग विभाग के श्री महेंद्र देसाई ने बेस्ट बैट्समैन का ख़िताब जीता। ऑपरेटिंग विभाग के श्री कार्तिक को मैन ऑफ द सीरीज का ख़िताब दिया गया।

मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के मार्गदर्शन में वीडीएसए द्वारा इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री नीरज धमीजा, वीडीएसए के सचिव श्री प्रदीप मीणा एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस एवं जबलपुर के बीच स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को समायोजित करने के उद्देश्य से ट्रेन संख्या 02133/02134 बांद्रा टर्मिनस–जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 02133 बांद्रा टर्मिनस–जबलपुर स्पेशल तथा ट्रेन संख्या 02134 जबलपुर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को अगली सूचना तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 02133 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 22 जनवरी, 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं के ऑनलाइन निवारण का जनवरी महीने का राज्य स्तरीय 'स्वागत' गुरुवार, 22 जनवरी को आयोजित होगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में हर महीने आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी-2026 का राज्य स्तरीय 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) गुरुवार, 22 जनवरी को आयोजित होगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2003 से शुरू हुए स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम के तहत हर महीने के चौथे गुरुवार को राज्य स्तरीय 'स्वागत' का आयोजन किया जाता है।

तदनुसार, जनवरी-2026 के राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम के लिए नागरिक अपना अभ्यावेदन गुरुवार, 22 जनवरी की सुबह 8.00 से 11.00 बजे के दौरान मुख्यमंत्री की जनसंपर्क इकाई, स्वर्णिम संकुल-2, गांधीनगर में व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार दोपहर बाद इस राज्य स्तरीय 'स्वागत' में स्वयं मौजूद रहकर नागरिकों की शिकायतें सुनेंगे।

अनुशासन का संदेश: सेल की सख्त कार्रवाई से ठेकेदारी व्यवस्था में हलचल

(जीएनएस)। देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने हाल के दिनों में एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए 21 फर्मों और ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि सार्वजनिक उपक्रमों में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है। सेल प्रबंधन ने यह कार्रवाई देशभर में फैली अपनी विभिन्न इकाइयों और कॉरपोरेट स्तर पर सामने आए गंभीर अनियमितताओं के मामलों के बाद की है, जिनमें अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन, जाली दस्तावेजों की प्रस्तुति, भ्रष्ट आचरण, असंतोषजनक प्रदर्शन और श्रमिकों के वेतन से जुड़ी गड़बड़ियां प्रमुख रूप से शामिल हैं।

सेल के इस फैसले से न केवल संबंधित ठेकेदारों और फर्मों में खलबली मच गई है, बल्कि अन्य कंपनियों और सेवा प्रदाताओं के लिए भी यह एक चेतावनी के रूप में सामने आया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करना केवल व्यावसायिक अवसर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और नियमों के प्रति प्रतिबद्धता की भी मांग करता है। सेल ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता, धोखाधड़ी या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे संबंधित फर्म कितनी ही बड़ी या प्रभावशाली क्यों न हो। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई भिलाई, राउरकेला, बोकारो और इस्को स्टील प्लांट के साथ-साथ सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेट कार्यालय से जुड़े मामलों में की गई है। अलग-अलग इकाइयों में जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर ठेकेदारों और फर्मों की भूमिका का मूल्यांकन किया गया और उसके बाद यह सख्त निर्णय लिया गया। सेल प्रबंधन का कहना है कि कंपनी की कार्यप्रणाली में गुणवत्ता, समयबद्धता और नैतिकता सर्वोपरि है, और जो भी इन मूल सिद्धांतों से समझौता करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। भिलाई स्टील प्लांट से सबसे अधिक 11 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि राउरकेला से चार, बोकारो से आठ और इस्को स्टील प्लांट से छह कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तीन ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की गई है। यह आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि समस्या किसी एक इकाई या क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि विभिन्न स्तरों पर अनुशासन और अनुपालन से जुड़ी खामियां सामने आईं।

सेल के निर्देशों के अनुसार इन फर्मों पर अलग-अलग अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ ठेकेदारों को 2026 से 2028 तक के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि कुछ पर वर्ष 2100 तक का स्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। स्थायी प्रतिबंध का निर्णय उन मामलों में लिया गया है, जहां अनियमितताएं गंभीर और बार-बार दोहराई गईं या जहां जाली दस्तावेजों और धोखाधड़ी जैसे मामलों में ठोस प्रमाण मिले। यह फैसला दर्शाता है कि सेल अब केवल अस्थायी चेतावनियों या हल्की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि भविष्य में ऐसे तत्वों को पूरी तरह से बाहर करने की नीति पर काम कर रहा है।

इस्को स्टील प्लांट के जनसंपर्क अधिकारी भास्कर कुमार ने बताया कि जिन फर्मों पर यह कार्रवाई हुई है, वे या तो अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहीं या जांच के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी पाए गए।

विश्व आर्थिक मंच : 2026, दावोस

गुजरात एआई, डिफेंस, टेक्सटाइल पार्क्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और इनोवेटिव फाइनेंसिंग जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों की तलाश कर रहा है : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

(जीएनएस)। गांधीनगर : विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की 56वीं वार्षिक बैठक 19 से 23 जनवरी, 2026 के दौरान स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हो रही है। इस वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए गुजरात की ओर से उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। यहां इंडिया पवेलियन के अंतर्गत देश के 10 राज्यों के प्रतिनिधिमंडल उपस्थित हैं, जो भारत में निवेश के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को पेश कर निवेशकों के साथ चर्चा करेंगे।

इस अवसर पर गुजरात की ओर से उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात सौभाग्यशाली है कि उसे शुरुआत से ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी

▸▸ विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन

▸▸ गुजरात की ओर से उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की बैठकें

▸▸ गुजरात सौभाग्यशाली है कि उसे शुरुआत से ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का लाभ मिला है, हम यहां गुजरात के लिए नए मौकों की तलाश में आए हैं : श्री हर्ष संघवी

नेतृत्व का लाभ मिला है और 2014 के बाद पूरा देश उनके नेतृत्व में विकास कर रहा है। अभी विश्व आर्थिक मंच में भारत का सबसे बड़ा और मजबूत प्रतिनिधिमंडल देखने को मिला है और जब हम तड़के यहां पहुंचे, तब पूरी दुनिया विश्राम में थी, लेकिन भारत के राज्यों के प्रतिनिधिमंडल सक्रिय रूप से निवेशकों के साथ बैठक में व्यस्त थे। यह हमारी प्रतिबद्धता, हमारी कार्य संस्कृति और देश के लोगों के प्रति हमारे नेतृत्व के समर्पण को दिखाता है।

निवेश के लिए गुजरात की क्षमता को उजागर करते हुए श्री हर्ष संघवी ने आगे कहा कि गुजरात में निवेश की मजबूत परंपरा रही है। वाइब्रेंट गुजरात 2024 में राज्य में 45 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए थे, और पिछले तीन महीनों में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत राज्य में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात का प्रतिनिधिमंडल यहां कुछ नया सीखने और नए अवसरों की तलाश में आया है।

श्री संघवी ने आगे कहा कि हम यहां अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधिमंडल के रूप में नहीं, बल्कि हम एक देश के रूप में एक ही एजेंडे के साथ यहां उपस्थित हैं। हम सभी यहां अपना कौशल, अपनी क्षमताएं और अपना सुशासन प्रस्तुत करेंगे। गुजरात राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिफेंस, टेक्सटाइल पार्क्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और इनोवेटिव फाइनेंसिंग जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों की तलाश कर रहा है।

फर्जी बिलों का जाल और 658 करोड़ का खेल बहु-राज्यीय जांच में ईडी का बड़ा शिकंजा

(जीएनएस)। देश में जीएसटी व्यवस्था को पारदर्शी और कर चोरी से मुक्त बनाने के दावों के बीच फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला एक बार फिर जांच एजेंसियों के सामने गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। अरुणाचल प्रदेश से जुड़े 658 करोड़ रुपये के कथित जीएसटी आईटीसी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को एक साथ कई राज्यों में छापेमारी कर पूरे कारोबारी नेटवर्क को हिला दिया। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई इस कार्रवाई में झारखंड, पश्चिम बंगाल और मणिपुर समेत कई स्थानों पर संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों के ठिकानों की तलाशी ली गई। यह अभियान न केवल राशि के लिहाज से बड़ा है, बल्कि इस बात का भी संकेत देता है कि फर्जी बिलिंग और टैक्स क्रेडिट के दुरुपयोग का नेटवर्क कितनी गहराई तक फैला हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, ईडी की यह कार्रवाई अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ी है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आईटीसी का अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया गया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि राकेश शर्मा और आशुतोष कुमार झा नामक दो व्यक्तियों ने बिना किसी वास्तविक वस्तु या सेवा की आपूर्ति किए बड़े पैमाने पर फर्जी बिल तैयार किए। इन बिलों के जरिए न केवल कागजों पर कारोबार दिखाया गया, बल्कि जीएसटी प्रणाली का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये का टैक्स क्रेडिट भी हासिल किया गया। यही राशि बाद में विभिन्न खातों और फर्मों के माध्यम से इधर-उधर घुमाई गई, जिससे धन शोधन का संदेह और गहराता चला गया।

जांच एजेंसियों का ध्यान विशेष रूप से 'सिद्धि विनायक ट्रेड मर्चेंट्स' नामक एक कथित फर्जी फर्म पर केंद्रित है। आरोप है कि इस फर्म के जरिए लगभग 658.55 करोड़ रुपये के जाली बिल जारी किए गए और इसके आधार पर करीब 99.31 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया। कागजों में यह सब वैध लेन-देन जैसा दिखता रहा, लेकिन जमीनी स्तर पर न तो कोई वास्तविक सप्लाई हुई और न ही कोई वास्तविक व्यापारिक गतिविधि। ईडी का मानना है कि यह फर्म केवल एक मुखौटा थी, जिसके पीछे पूरा नेटवर्क सक्रिय था।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े करीब 58 अन्य फर्जी कारोबारी प्रतिष्ठान विभिन्न राज्यों में सक्रिय थे। ये सभी आपस में जुड़े हुए थे और एक-दूसरे को फर्जी बिल जारी कर जीएसटी प्रणाली को भ्रमित करने का काम कर रहे थे। इस नेटवर्क की खास बात यह थी कि अलग-अलग राज्यों में छोटी-छोटी फर्मों और कंपनियों के नाम पर कारोबार दिखाया जाता था, जिससे संदेह कम हो और जांच एजेंसियों की नजर से बचा जा सके।

हिंदुत्व जीवन का संस्कार है, देशहित किसी एक का नहीं बल्कि सबका दायित्व: राजकोट में संघ प्रमुख मोहन भागवत

(जीएनएस)। राजकोट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आयोजित प्रमुख जन गोष्ठी केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विचार और आत्ममंथन का मंच बन गई। सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों के बीच सरसंघचालक मोहन भागवत ने जो कहा, वह समकालीन भारत की वैचारिक दिशा, सामाजिक जिम्मेदारी और सांस्कृतिक आत्मबोध को समझने का अवसर देता है। सेवा भारती भवन में हुई इस गोष्ठी में संघ प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देशहित पर किसी व्यक्ति, संगठन या विचारधारा का एकाधिकार नहीं हो सकता। राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व सामूहिक है और जो भी इस भावना से कार्य करता है, संघ उसके साथ खड़ा है।

मोहन भागवत ने संघ की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि अनेक उपेक्षाओं, विरोधों और प्रतिबंधों के बावजूद संघ आज जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, वह किसी सत्ता या साधन का परिणाम नहीं, बल्कि हिंदू समाज के आशीर्वाद और विश्वास का फल है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संघ स्वयं को किसी राजनीतिक या वैचारिक रिमोट कंट्रोल के रूप में नहीं देखता। संघ का कार्य प्रेम, आत्मीयता और विश्वास पर आधारित है। स्वयंसेवक तैयार किए जाते हैं, आदेश मानने वाली मशीनें नहीं। शाखाओं के माध्यम से संस्कार दिए जाते हैं, विवेक विकसित किया जाता है और फिर वही स्वयंसेवक अपने अनुभव, समझ और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार समाज हित में निर्णय लेते हैं।

संघ प्रमुख ने यह भी रेखांकित किया कि जो लोग देशहित में कार्य कर रहे हैं, चाहे वे संघ से औपचारिक रूप से जुड़े हों या नहीं, संघ उन्हें अपना ही स्वयंसेवक मानता है। यह विचार संघ की

उस व्यापक दृष्टि को दर्शाता है, जिसमें संगठन से अधिक उद्देश्य को महत्व दिया जाता है। देश की सेवा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, बल्कि भाव और कर्म से तय होती है।

हिंदुत्व को लेकर मोहन भागवत का वक्तव्य भी स्पष्ट और वैचारिक रूप से मजबूत था। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व कोई संकीर्ण धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि जीवन पद्धति है। यही वह जीवन दृष्टि है, जिसके आधार पर भारत का संविधान बना है और उसी पद्धति से संघ कार्य करता है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होने का अर्थ किसी पंथ या संप्रदाय का वर्चस्व नहीं, बल्कि सभी पंथों और मतों का सम्मान और स्वागत है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा 'वसुधैव कुटुंबकम' में बसती है, जहां पूरी दुनिया को एक परिवार माना जाता है। यही सच्चा वैश्वीकरण है। अन्य देशों की सोच दुनिया को एक बाजार बनाने की रही है, जबकि भारतीय दृष्टि दुनिया को एक परिवार के रूप में देखने की रही है।

मोहन भागवत ने आज की युवा पीढ़ी, खासकर जेन-जी को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आज का युवा एक 'कोरी स्लेट' की तरह है। वह ईमानदार है, प्रश्न करता है और अपनी शर्तों पर सत्य को समझना चाहता है। ऐसे में पुराने तरीकों से संवाद करने के बजाय हमें उनसे बात करने की नई कला सीखनी होगी। उन्होंने सोशल मीडिया की भूमिका पर भी चेताया और कहा कि तकनीक का उपयोग हमारे हाथ में होना चाहिए। हमें सोशल मीडिया का मालिक बनना चाहिए, उसे अपना मालिक नहीं बनने देना चाहिए। यदि विचारों की दिशा तय नहीं होगी, तो माध्यम हमें बहा ले जाएगा। पड़ोसी देशों का उल्लेख करते हुए संघ प्रमुख ने एक गंभीर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास के देशों में हिंदू-मुस्लिम वैमनस्य को फिर से हवा दी जा रही है। यह विभाजनकारी सोच भारत में न फैले, इसके लिए समाज को सजग और जागरूक रहना होगा। भारत की ताकत उसकी विविधता में एकता है और इसे कमजोर करने वाली किसी भी सोच को समय रहते पहचानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द केवल कानून से नहीं, बल्कि समाज की चेतना से सुरक्षित रहता है।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोहन भागवत ने इसे केवल व्यवस्था की समस्या मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का मूल कारण व्यवस्था से ज्यादा मनुष्य के मन में है। जब तक व्यक्ति का संस्कार नहीं होगा, तब तक केवल नियम-कानून भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते। संस्कारित व्यक्ति ही ईमानदार व्यवस्था का निर्माण करता है। यही कारण है कि संघ व्यक्ति निर्माण पर जोर देता है, क्योंकि समाज और राष्ट्र का चरित्र व्यक्तियों से ही बनता है।

पूरे संबोधन में यह स्पष्ट दिखाई दिया कि संघ प्रमुख का जोर टकराव या विरोध की भाषा पर नहीं, बल्कि संवाद, संस्कार और सामूहिक जिम्मेदारी पर था। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार या किसी संगठन का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की भूमिका उसमें निहित है। देश को आगे बढ़ाने के लिए विचार, व्यवहार और चरित्र—तीनों स्तरों पर काम करना होगा। राजकोट की इस गोष्ठी में मोहन भागवत के विचार केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने समकालीन भारत के सामने खड़े सामाजिक, वैचारिक और सांस्कृतिक प्रश्नों पर एक व्यापक दृष्टि प्रस्तुत की। हिंदुत्व को जीवन पद्धति के रूप में समझना, देशहित को साझा जिम्मेदारी मानना, युवा पीढ़ी से संवाद करना, विभाजनकारी विचारों से सावधान रहना और भ्रष्टाचार को व्यक्ति के संस्कार से जोड़कर देखना—ये सभी बातें मिलकर उस भारत की तस्वीर पेश करती हैं, जिसकी कल्पना संघ करता है।

यह संबोधन इस बात का संकेत भी है कि संघ शताब्दी वर्ष को केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और दिशा निर्धारण के अवसर के रूप में देख रहा है। राजकोट से दिया गया यह संदेश न सिर्फ संघ कार्यकर्ताओं के लिए, बल्कि व्यापक समाज के लिए भी एक विचारोत्तेजक आह्वान बनकर सामने आया है।

अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस देने की कार्रवाई पर अजय राय का विरोध, संत समाज के प्रति असम्मान बताया

(जीएनएस)। जौनपुर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रयागराज में आयोजित माघ मेला के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस दिए जाने की कार्रवाई की तीखी आलोचना की है। उन्होंने इसे न केवल अनुचित बल्कि संत समाज के प्रति असम्मानजनक करार दिया। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से संत-महात्माओं के सम्मान में खड़ी रही है और इस तरह की कार्रवाई धार्मिक और सामाजिक भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता की कमी को दर्शाती है। एक कार्यक्रम में भाग लेने जौनपुर आए अजय राय ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लोग शंकराचार्य के रूप में मानते हैं और उनके साथ प्रशासन द्वारा किया गया यह व्यवहार निंदनीय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संत समाज और धार्मिक गुरुओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार होना चाहिए और प्रशासनिक निर्णयों में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी धार्मिक व्यक्तित्व या समाज को अपमानित न किया जाए। अजय राय ने इस अवसर पर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों और आगामी चुनाव की तैयारियों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और प्रदेश की सभी 403 सीटों पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन से जुड़े किसी भी निर्णय को केवल केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर लिया जाएगा और स्थानीय स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट होकर काम करने का निर्देश दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बयान के जरिए कांग्रेस न केवल संत समाज के प्रति अपनी संवेदनशीलता को दर्शा रही है, बल्कि आगामी चुनाव में धार्मिक और सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में करने की रणनीति भी तैयार कर रही है। अजय राय का यह कदम प्रशासन और सरकार को सतर्क करने के साथ-साथ जनता के बीच कांग्रेस की संवेदनशील छवि को मजबूत करने की दिशा में भी माना जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक आयोजनों और मेलों में प्रशासन का प्रमुख कार्य सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना होना चाहिए, न कि किसी संत या धार्मिक गुरु को नोटिस देने जैसी कार्रवाई करना। अजय राय ने स्पष्ट किया कि ऐसे नोटिस से न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, बल्कि समाज में असंतोष और विवाद भी पैदा हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया कि संत समाज और धार्मिक नेताओं के प्रति सम्मान बनाए रखना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा से धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील रही है और इस दिशा में आने वाले समय में भी इसी तरह के मामलों में आवाज बुलंद करती रहेगी। जौनपुर में अजय राय के इस बयान को स्थानीय लोगों और राजनीतिक वर्ग ने ध्यानपूर्वक सुना। उनका कहना है कि प्रशासनिक कार्यवाही में संत समाज के प्रति सम्मान बनाए रखना बेहद आवश्यक है और किसी भी स्थिति में धार्मिक नेताओं को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। उनके इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि संत और धार्मिक समुदाय का समर्थन चुनावी रणनीतियों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

नोएडा हादसा: बेसमेंट में कार गिरने से हुई मौत, तीन सदस्यीय कमेटी ने शुरू की जांच

(जीएनएस)। नोएडा। सेक्टर-150 में निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में गहरे और पानी से भरे गड्ढे में कार गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय समिति इस हादसे की पूरी घटना और जिम्मेदारियों का विश्लेषण करेगी। जांच समिति का नेतृत्व मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर कर रहे हैं। समिति ने घटना स्थल का दौरा करने के साथ ही नोएडा विकास प्राधिकरण (नोएडा प्राधिकरण) के संबंधित अधिकारियों से जानकारी एकत्रित की और मृतक युवराज के परिजनों से मुलाकात कर उनकी बात सुनी। समिति का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि हादसा लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी या निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट की संरचनात्मक कमजोरियों के कारण हुआ।

मिली जानकारी के अनुसार हादसा सेक्टर-150 की उस मॉल के बेसमेंट में हुआ, जहां निर्माण कार्य चल रहा था। गड्ढा गहरा होने के साथ-साथ पानी से भरा हुआ था, जिससे कार में सवार युवराज की तुरंत ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में असामाजिक भीड़ के बीच विरोध प्रदर्शन हुए। स्थानीय निवासी और सोसाइटियों के लोग नोएडा प्राधिकरण और निर्माण कंपनी की लापरवाही को लेकर नाराज हैं।

सूरत में ज़हर का काला कारोबार बेनकाब, करोड़ों की डील से पहले कोबरा विष तस्करी का पर्दाफाश

(जीएनएस)। सूरत। हीरे और कपड़ा उद्योग के लिए पहचाने जाने वाले सूरत शहर में उस समय सनसनी फैल गई, जब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक खतरनाक अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए कोबरा सांप के जहर की तस्करी का भंडाफोड़ किया। यह मामला न केवल रकम के लिहाज से चौंकाने वाला है, बल्कि इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसमें प्रतिबंधित और अत्यंत घातक वन्य जीव उत्पाद की अवैध खरीद-फरोख्त सामने आई है। SOG की कार्रवाई में करीब 6.5 मिलीलीटर बैन कोबरा का जहर बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग छह करोड़ रुपये आंकी जा रही है, जबकि तस्कर इसे करीब नौ करोड़ रुपये में बेचने की तैयारी में थे। इस पूरे ऑपरेशन में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी सांप के जहर की जब्ती मानी जा रही है। मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि कोबरा का जहर पूरी तरह प्रतिबंधित श्रेणी में आता है और इसका अवैध व्यापार न केवल वन्य जीव संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि यह सीधे तौर पर मानव जीवन के लिए भी बड़ा खतरा पैदा करता है। इस जहर का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजारों में नशे, रेव पार्टियों और तथाकथित 'स्नेक बाइट हाई' जैसे जानलेवा प्रयोगों में किया जाता रहा है, जिसके चलते कई देशों में इस पर सख्त निगरानी और प्रतिबंध लागू हैं।

SOG को इस गिरोह के बारे में गुप्त सूचना मिली थी कि सूरत में एक संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जो कोबरा के जहर की बड़ी खेप बेचने की तैयारी कर रहा है। सूचना मिलते ही SOG ने इसे हल्के में लेने के बजाय एक विस्तृत और गोपनीय रणनीति तैयार की। शहर के अलग-अलग इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई और तकनीकी इनपुट के साथ-साथ मानवीय खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया। पुलिस को जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि तस्कर बेहद शातिर तरीके से सौदे को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, ताकि किसी को शक न हो। इस ऑपरेशन का सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला पहलू यह था कि SOG के एक पुलिस निरीक्षक ने खुद को बड़ा खरीदार बताकर तस्करों से संपर्क किया। उसने करोड़ों रुपये की पेशकश करते हुए सौदे को अंतिम रूप देने की बातचीत शुरू की। तस्करों को विश्वास दिलाया गया कि खरीदार अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा है और उन्हें तय कीमत पर पूरा माल चाहिए। लंबी बातचीत और भरोसे के बाद आरोपियों ने सौदे के लिए सूरत के सरथाना इलाके को चुना और मिलने की जगह के तौर पर 'पटेल लाइफ पार्टनर' नाम के एक मैरिज ब्यूरो कार्यालय को तय किया। तस्करों को लगा कि इस तरह की जगह पर किसी को शक नहीं होगा और सौदा आसानी से निपट जाएगा। निर्धारित समय पर जैसे ही सभी आरोपी वहां इकट्ठा हुए, पहले से पूरी तैयारी में मौजूद SOG की टीम ने अचानक छापा मार दिया। कुछ ही पलों में पूरे कार्यालय को घेर लिया गया और आरोपियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। तलाशी के दौरान कोबरा का अत्यंत घातक जहर बरामद किया गया, जिसे बेहद सावधानी से सील कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद इस जहर की कीमत करोड़ों में है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में इसकी मांग बहुत अधिक है और इसकी उपलब्धता बेहद सीमित।

गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों में सूरत और वडोदरा के रहने वाले लोग शामिल हैं। सूरत से मनसुखभाई अंबाभाई घिनैया और चिमनभाई छगनभाई भुवा को पकड़ा गया है, जबकि वडोदरा से समीर जयंतीलाल पांचाल, प्रवीण कांतिलाल शाह, केतनभाई चित्तरंजनभाई शाह, मकरंदभाई श्रीकांतभाई कुलकर्णी और प्रशांत राजेशभाई शाह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये सभी आरोपी आपस में संपर्क में थे और लंबे समय से इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहे थे। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि सौदे की कुल कीमत करीब 9.10 करोड़ रुपये तय की गई थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह गिरोह कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सांप के जहर का इस्तेमाल कानूनी रूप से केवल बेहद सीमित परिस्थितियों में, मेडिकल और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जा सकता है और वह भी सख्त सरकारी अनुमति के तहत। इसके विपरीत, अवैध बाजार में इसका उपयोग नशे के लिए, खतरनाक प्रयोगों में और ऐसे आयोजनों में किया जाता है, जहां लोग जानबूझकर जिंदा सांप से कटवाकर कथित 'रोमांच' या 'नशे' का अनुभव करते हैं। इस तरह की गतिविधियां न केवल अपराध हैं, बल्कि सीधे तौर पर मानव जीवन और वन्य जीवों दोनों के लिए घातक हैं। इस मामले में पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि एक आरोपी, घनश्याम सोनी, अभी फरार है। माना जा रहा है कि जहर की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अहम सुराग उसी के पास हो सकते हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो पाएगा कि कोबरा का जहर आखिर कहां से लाया गया था, इसे किस तरह निकाला गया और किन-किन रास्तों से इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की योजना थी। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क के तार सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों और संभवतः विदेशों से भी जुड़े हो सकते हैं।

भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी टंकी भरते ही ढही, 21 करोड़ का सपना मलबे में बदला

(जीएनएस)। सूरत। विकास के नाम पर खड़े किए जा रहे बड़े-बड़े ढांचों की हकीकत क्या है, इसका डरावना उदाहरण सूरत जिले के मांडवी तालुका के तड़केश्वर गांव में तड़के सामने आया, जब करोड़ों रुपये की लागत से बनी पानी की टंकी उद्घाटन से पहले ही भरभराकर जमीन पर आ गिरी। 'गाय पाक पानी सन्याल योजना' के तहत बनाई जा रही 11 लाख लीटर क्षमता की यह टंकी जैसे ही ट्रायल के दौरान पानी से भरी गई, वैसे ही भ्रष्टाचार और लापरवाही की पूरी कहानी मलबे के साथ बाहर आ गई। इस हादसे में एक महिला समेत तीन मजदूर घायल हो गए, जिन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। गनीमत यह रही कि यह दुर्घटना ट्रायल के दौरान हुई, अन्यथा उद्घाटन के बाद अगर यह टंकी ढहती, तो दर्जनों जानें जा सकती थीं। तड़केश्वर गांव और आसपास के इलाकों में यह टंकी 33 गांवों को पीने का पानी देने के उद्देश्य से बनाई जा रही थी। करीब 15 मीटर ऊंची इस विशालकाय संरचना पर सरकार के लगभग 21 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। वर्षों से पानी की किल्लत झेल रहे ग्रामीण इस टंकी को उम्मीद की नजर से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही टेस्टिंग के लिए इसमें करीब 9 लाख लीटर पानी भरा गया, पूरा स्ट्रक्चर अचानक चरमराने लगा और कुछ ही पलों में यह विशाल टंकी मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। तेज धमाके जैसी आवाज के साथ जब

टंकी गिरी, तो आसपास मौजूद मजदूर और ग्रामीण सहम गए। धूल का गुबार छा गया और चीख-पुकार मच गई।

हादसे के बाद जब लोग मौके पर पहुंचे और मलबे को देखा, तो गुस्सा और भी भड़क उठा। टूटे हुए कंक्रीट के टुकड़ों से सीमेंट की परतें ऐसे उखड़ रही थीं, जैसे रेत और मिट्टी का ढेर हो। लोहे की सरियों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट में शुरुआत से ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और निर्माण के दौरान भारी भ्रष्टाचार हुआ। लोगों का कहना है कि अगर निर्माण सही तरीके से हुआ होता, तो ट्रायल के दौरान ही यह टंकी कभी नहीं गिरती। यह हादसा सिर्फ एक टंकी के गिरने का मामला नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर सवाल है, जिसमें ठेकेदार, इंजीनियर और निगरानी एजेंसियां शामिल होती हैं। 21 करोड़ रुपये की सार्वजनिक राशि से बने प्रोजेक्ट का इस तरह ढह जाना यह दिखाता है कि फाइलों में सब कुछ ठीक दिखाने और ज़मीन पर घटिया काम कराने का खेल किस हद तक फैल चुका है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर हर बार बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में न तो गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है और न ही जनता की सुरक्षा पर। घटना की सूचना मिलने के बाद वॉटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी देर से मौके पर पहुंचे, जिसको लेकर भी लोगों में नाराजगी देखी गई। विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जय चौधरी ने बयान दिया कि टंकी अभी अंडर ट्रायल थी और पूरे मामले की तकनीकी जांच के लिए सूरत के SVNIT के इंजीनियरों की एक टीम गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार ठेकेदार और अन्य दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ग्रामीणों को यह बयान महज औपचारिकता लगा, क्योंकि इससे पहले भी कई मामलों में जांच के नाम पर फाइलें दबा दी गईं और दोषियों को बचा लिया गया।

ग्रामीणों का सवाल सीधा है—जब टंकी का उद्घाटन भी नहीं हुआ था और ट्रायल के दौरान ही यह गिर गई, तो क्या निर्माण के दौरान कभी कोई गुणवत्ता जांच हुई थी? क्या इंजीनियरों और कंसल्टेंट्स ने समय-समय पर साइट का निरीक्षण किया था या सिर्फ कागजों पर ही सब कुछ पास कर दिया गया? लोगों का कहना है कि अगर उद्घाटन के बाद टंकी चालू हो जाती और फिर कभी यह हादसा होता, तो इसका खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता।

हादसे के बाद गांव और आसपास के इलाकों में भारी आक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने मांग की कि इस मामले में सिर्फ विभागीय जांच ही नहीं, बल्कि आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। उनका कहना है कि यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया भ्रष्टाचार है, जिसमें सार्वजनिक धन की खुली लूट हुई है। लोगों ने सवाल उठाया कि 21 करोड़ रुपये आखिर कहां गए, अगर एक पानी की टंकी भी ढंग से नहीं बन सकी।

प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कदम उठाए। संबंधित डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी के सभी भुगतान पर रोक लगा दी गई है।

सोना वायदा में 4469 रुपये और चांदी वायदा में 14625 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा 31 रुपये तेज

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 399151.87 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 121826.48 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 277302.02 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 41869 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 6632.25 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 112484.63 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 145775 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 152500 रुपये और नीचे में 145500 रुपये पर पहुंचकर, 145639 रुपये के पिछले बंद के सामने 4469 रुपये या 3.07 फीसदी की तेजी के संग 150108 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 4647 रुपये या 3.94 फीसदी की मजबूती के साथ 122600 रुपये प्रति 8 ग्राम बोला गया। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 634 रुपये या 4.29 फीसदी की मजबूती के साथ 15424 रुपये प्रति 1 ग्राम बोला गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 145389 रुपये के भाव पर खूलकर, 152545 रुपये के दिन के उच्च और 144811 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 4680 रुपये या 3.22 फीसदी की मजबूती के साथ 149907 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 145569 रुपये के भाव पर खूलकर, 154145 रुपये के दिन के उच्च और 145420 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 145420 रुपये के पिछले बंद के सामने 5259 रुपये या 3.62 फीसदी की मजबूती के साथ 150679 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 306499 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 327998 रुपये और नीचे में 306499 रुपये पर पहुंचकर, 310275 रुपये के पिछले बंद के सामने 14625 रुपये या 4.71 फीसदी बढ़कर 324900 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 15330 रुपये या 4.91 फीसदी की मजबूती के साथ 327757 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 121826.48 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 277302.02 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 112484.63 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 41869 पॉइंट के स्तर पर

फरवरी वायदा 15275 रुपये या 4.89 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 327741 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

मेटल वर्ग में 5333.27 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 9.55 रुपये या 0.73 फीसदी गिरकर 1292.95 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा रु.1.15 या 0.37 फीसदी औंधकर 313.15 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.75 रुपये या 0.55 फीसदी औंधकर 315.85 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 45 पैसे या 0.23 फीसदी की नरमी के साथ 191.4 रुपये प्रति किलो बोला गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4003.85 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5421 रुपये के भाव पर खूलकर, 5455 रुपये के दिन के उच्च और 5368 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 31 रुपये या 0.57 फीसदी की तेजी के संग 5453 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 32 रुपये या 0.59 फीसदी की तेजी के संग 5454 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 324.7 रुपये के भाव पर खूलकर, 349 रुपये के दिन के उच्च और 322.9 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 332.8 रुपये के पिछले बंद के सामने 15.1 रुपये या 4.54 फीसदी की बढ़त के साथ 347.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 15.2 रुपये या 4.57 फीसदी की बढ़त के साथ 347.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 974 रुपये के भाव पर खूलकर, 5 रुपये या 0.52 फीसदी लुढ़ककर 956.5 रुपये प्रति किलो बोला गया। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 54212.30 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 58272.33 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4617.11 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 396.85 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 72.56 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 234.74 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 582.37 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 3409.54 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 3.96 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.20 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 20686 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 77889 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 28155 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 416567 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 47729 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14609 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 40627 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 104868 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17013 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 38341 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 40272 पॉइंट पर खूलकर, 42688 के उच्च और 40272 के नीचले स्तर को छूकर, 1597 पॉइंट बढ़कर 41869 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 24.8 रुपये की बढ़त के साथ 271.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.75 रुपये की बढ़त के साथ 13.45 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 148000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 2859.5 रुपये की बढ़त के साथ 3790.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 320000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 10455 रुपये की बढ़त के साथ 18400 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6.53 रुपये की गिरावट के साथ 11.99 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 55 पैसे की नरमी के साथ 1.53 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 21.2 रुपये की गिरावट के साथ 209.2 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 776 रुपये की गिरावट के साथ 780 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3646.5 रुपये की गिरावट के साथ 5537 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.51 रुपये की बढ़त के साथ 19.29 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 32 पैसे की नरमी के साथ 0.34 रुपये हुआ।